Result Mitra Daily Magazine

अमेरिकी कांग्रेस (संसद) द्वारा रिजॉल्व तिब्बत एक्ट (Resolve Tibbet Act)

हालिया सन्दर्भ -

- हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस (संसद) द्वारा रिजॉल्व तिब्बत एक्ट (Resolve Tibbet Act) पारित किया गया है, जो USA द्वारा पूर्व में तिब्बत संबंधित पारित किए गए दो अधिनियमों से ज्यादा सहायक है।
- USA की कांग्रेस द्वारा 12 जून को तिब्बत चीन विवाद समाधान अधिनियम पारित किया गया है, जिसे तिब्बत समाधान अधिनियम नाम दिया गया है।
- जो बाइडेन के सहमति देते ही यह अधिनियम बन जाएगा।
- इससे पहले कांग्रेस ने तिब्बती नीति अधिनियम या TPA, 2002 एवं तिब्बती नीति एवं समर्थन अधिनियम यानि TPSA 2020 पारित किया है।
-

Resolve Tibbet Act के मुख्य प्रावधान -

- यह एक्ट तिब्बत के बारे में चीनी दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए धन की उपयोग को समर्थन देता है।
- चीनी दुष्प्रचार का तात्पर्य तिब्बत के इतिहास तिब्बती संस्थानों में दलाई लामा सहित तिब्बती लोगों के बारे में दुष्प्रचार से है।
- इस एक्ट में चीन के उस दावे को भी चुनौती दी गई है कि तिब्बत प्राचीन काल से ही चीन का अभिन्न हिस्सा रहा है।

- इस एक्ट में चीन के साथ तिब्बती समुदाय के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधि एवं दलाई लामा के मध्य बिना पूर्व शर्त के सार्थक बातचीत का भी समर्थन करता है ताकि विवाद का हल निकाला जा सके।
- यह एक्ट तिब्बती लोगों के विशेष धार्मिक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पहचान को भी समर्थन देता है तथा TPA, 2002 में परिभाषित स्वायत्त तिब्बती क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रों में भी संशोधन करता है।

पूर्व के कानून से अलग –

- वास्तव में TPA 2002 तिब्बत संबंध में USA का पहला कानून था, जिसमें तिब्बतियों के साथ चीन द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार को तो चिन्हित किया, लेकिन 2024 के एक्ट के विपरीत तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग माना।
- TPA, 2002 के द्वारा दलाई लामा को चीन के साथ एक रचनात्मक भागीदार के रूप में बातचीत का समर्थन किया लेकिन तिब्बत के संप्रभुता एवं स्वतंत्रता संबंधी तथ्यों का समर्थन नहीं किया।
- TPA ने स्पष्टतः वर्णित किया कि USA ने तिब्बत के निर्वासित सरकार के साथ कोई आधिकारिक संबंध नहीं बनाया और वह दलाई लामा से सिर्फ एक नोबेल पुरस्कार विजेता एवं आध्यात्मिक गुरु के रूप में मिला।
- TPSA, 2020 के जरिए USA ने दलाई लामा एवं चीन के बीच रचनात्मक बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिससे तिब्बत को अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिला।
- नए एक्ट इस बात पर जोर देता है कि चीन दलाई लामा के साथ बिना पूर्व शर्त के बातचीत करे एवं समस्या का समाधान ढूंढे।
- TPSA 2020 ने यह भी कहा था कि दलाई लामा के उत्तराधिकार का मामला चीन के चिंता का विषय नहीं होना चाहिए तथा वह इसे बौद्ध लोगों (तिब्बती) पर छोड़ दे।

तिब्बत चीन मुद्दा -

- तिब्बत पृथ्वी पर औसतन मामले सबसे ऊंचा क्षेत्र है जिनकी औसत ऊंचाई 4900 मीटर है।
- दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नेपाल तिब्बत की सीमा पर ही है।
- तिब्बत का क्षेत्रफल लगभग 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर है जो चीन के कुल क्षेत्रफल का एक चौथाई है।
- 13 वें दलाई लामा तू (थुबेटन गथातसो) ने वर्ष 1913 में तिब्बत के स्वतंत्रता की घोषणा की। हालांकि चीन ने इसे मान्यता नहीं दी एवं इस क्षेत्र पर अपने दावे को बरकरार रखा।

Result Mitra

- वर्ष 1912 से लेकर 1949 तक, जिस वर्ष पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, तब तक किसी भी चीनी सरकार ने तिब्बत को अपने अधीन नहीं रखा।
- वर्ष 1951 तक स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र पर दलाई लामा के सरकारों ने शासन किया।
- वर्ष 1950 - 51 में माओत्से तुंग के शासनकाल में चीनी सेना ने तिब्बत को प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया।
- वर्ष 1951 में तिब्बती नेताओं एवं चीन के बीच एक 17 सूत्री समझौता हुआ, जिसके तहत तिब्बत की राजधानी में चीनी सैन्य एवं सिविल मुख्यालय खोले जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- हालांकि दलाई लामा एवं अन्य तिब्बती नेता ने इसे अमान्य करार दिया क्योंकि यह संधि थोपी गई थी।
- वर्ष 1959 में तिब्बती विद्रोह के फलस्वरुप दलाई लामा एवं अनुयायियों को निर्वासित होकर भारत आना पड़ा।
- इन्होंने धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में एक निर्वासित सरकार का गठन किया, जिसे 'केंद्रीय तिब्बती प्रशासन' कहा जाता है।
- दलाई लामा के निर्वासित होने के बाद चीन ने तिब्बती क्षेत्र पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली।

भारत की तिब्बत नीति -

- सदियों से तिब्बत भारत का अच्छा पड़ोसी रहा है।
- भारत चीन की अधिकांश सीमा वास्तव में भारत तिब्बत के बीच ज्यादा भाग में है, जो लगभग 3500 किमी लंबी है।
- वर्ष 1914 में तिब्बती, भारतीय (ब्रिटिश) एवं चीनी प्रतिनिधियों के द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर के माध्यम से सीमाओं का निर्धारण किया गया, जिसे 'मैकमोहन रेखा' कहा गया।
- वर्ष 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर पूर्ण अधिकार कर लिया तो उसने मैकमोहन रेखा एवं शिमला सम्मेलन दोनों को निरस्त कर दिया।
- भारत एवं चीन के बीच वर्ष 1954 में एक समझौता हुआ जिसमें भारत ने तिब्बत को चीन के तिब्बत क्षेत्र के रूप में मान्यता दी।
- वर्ष 1959 में जब दलाई लामा भारत आए तो नेहरू ने उन्हें आश्रय देने एवं निर्वासित सरकार की स्थापना करने में मदद की।
- मोदी सरकार में तिब्बत नीति में कुछ बदलाव आया और 2014 के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी ने तिब्बत के निर्वासित सरकार प्रमुख लोबसंग सांगे को आमंत्रण दिया। हालांकि 2019 के समारोह में मोदी ने ऐसा नहीं किया ताकि मोदी जिनपिंग की निर्धारित शिखर वार्ता सुगमता से संपन्न हो।

दलाई लामा -

Rishit Mitra

- ऐसा माना जाता है कि दलाई लामा और अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व एवं तिब्बत के संरक्षण संत के प्रतीक चिन्ह हैं।
- अभी तक कुल 14 दलाई लामा हुए हैं जिनमें पहले एवं दूसरे को यह उपाधि मारणोप्रांत दी गई थी।
- दलाई लामा का संबंध बौद्ध धर्म की गेलुप्पा परंपरा से संबंध रखता है, जो तिब्बत में सबसे प्रभावशाली परंपरा है।
- 14 में एवं वर्तमान दलाई लामा का वास्तविक नाम तेनजिंग ग्यातसो है।

Resut Mitra